



ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU FOR BPSK EXAMINATION

HINDI

DATE

18/08/2023

THE HINDU National

➔ चंद्रयान प्रणोदन, लैंडर मॉड्यूल अलग

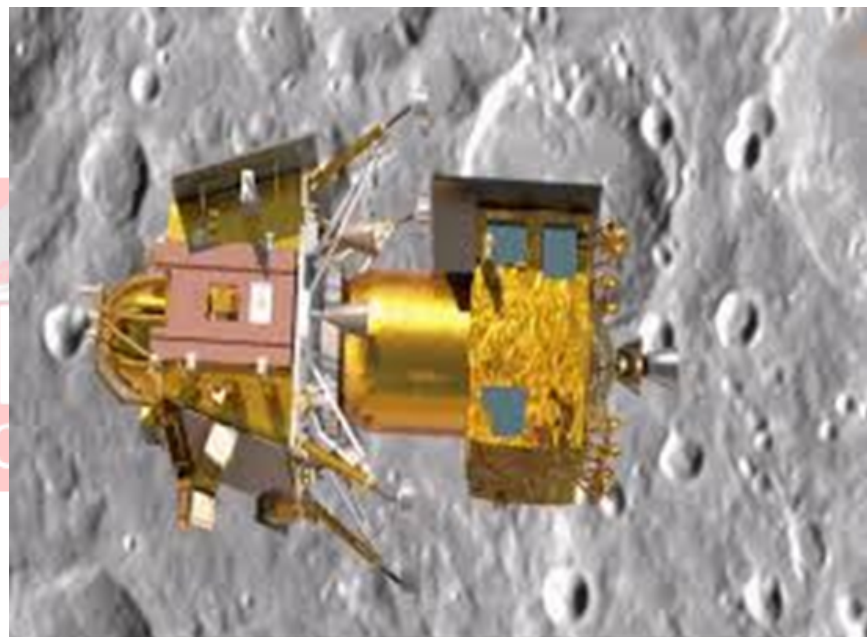
चंद्रयान 3 विमान में 34 दिनों के बाद, प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाता है।

प्रोपल्शन मॉड्यूल - जीएसएलवी बंद होने के बाद चलने के लिए बिजली की आपूर्ति करने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है।

लैंडर मॉड्यूल - इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं। लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। एक बार जब लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा, तो रोवर लैंडर से बाहर आ जाएगा और चंद्रमा की सतह पर रासायनिक प्रयोग करेगा। लैंडर मॉड्यूल वर्तमान में चंद्रमा की अंतिम कक्षा में है, यानी चंद्रमा की सतह से 100 किमी की ऊंचाई पर है।

इसरो चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला।

Separation of lander and propulsion module



➔ अब कोई थोक सिम कार्ड नहीं सरकार। धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए कदम।

धोखाधड़ी से प्राप्त सिम कार्ड के माध्यम से किए गए साइबर धोखाधड़ी को कम करने के लिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी) अब सिम डीलरों के पंजीकरण और "निर्विवाद सत्यापन" को अनिवार्य करेगा, इसकी घोषणा गुरुवार को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की थी।

धोखाधड़ी वाले कनेक्शनों पर अंकुश लगाने के हालिया प्रयासों के कारण 67,000 सिम डीलरों, 52 लाख कनेक्शनों को काली सूची में डाला गया है और 300 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं।

"डेटा और सबूत... हमें पता चला कि साइबर धोखाधड़ी में डीलरों की मिलीभगत होती है, जहां हमलावर थोक में (मोबाइल) नंबर खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल कॉल करने और लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं, और तुरंत दूसरे नंबर पर चले जाते हैं, सिम डीलर मिल जाते हैं इन कृत्यों में शामिल होने पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।"उसने कहा

नई प्रणाली

सिम कनेक्शन प्रदान करने की सुविधा बंद की जा रही है और इसके स्थान पर एक "व्यवसाय" मॉडल रखा जा रहा है, जहां सिम जारी करते समय उन्हें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) करना होगा।

थोक उपयोगकर्ताओं को एक संक्रमण अवधि प्रदान की जाएगी। सरकार, रक्षा और कानून प्रवर्तन के थोक ग्राहकों को इससे छूट मिलती रहेगी।

➔ अब मनरेगा कार्यस्थलों पर उत्पादित संपत्तियों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए ड्रोन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत कार्यस्थल पर अपनी निगरानी बढ़ाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय काम की प्रगति और गुणवत्ता दोनों की निगरानी के लिए ड्रोन की सेवा में दबाव डालेगा।

मंत्रालय द्वारा जारी प्रक्रियाओं के मानकों के अनुसार, ड्रोन का उपयोग चार प्रकार की निगरानी के लिए किया जाएगा; चल रहे कार्य का सर्वेक्षण करना; पूर्ण किए गए कार्य का निरीक्षण करना, प्रभाव का आकलन करना और शिकायतों के मामले में विशेष निरीक्षण करना।

"मनरेगा कार्य में भ्रष्टाचार के कई मामले हैं जहां श्रमिकों के स्थान पर मशीन का उपयोग किया जा रहा है, कई को बिना काम किए मजदूरी मिलती है, या स्वीकृत सूची से परे काम किया जा रहा है, इत्यादि। ड्रोन ऐसे में मददगार होंगे। वास्तविक समय के लिए असम निगरानी और साक्ष्य जुटाने के लिए," मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

हर जिले के अंदर लोकपाल द्वारा ड्रोन का उपयोग किया जाएगा, शिकायतों और उसके निपटान के लिए लोकपाल जिम्मेदार है।

लोकपाल ड्रोन की सुविधा का वस्तुतः उपयोग करेगा। डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए ड्रोन से एकत्र किए गए वीडियो और तस्वीरों को संग्रहीत करने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा।

➔ CJI ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता चाहते हैं कि SC अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में सरकार की 'बुद्धिमत्ता' का आकलन करे।

SC ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर उन्होंने कहा कि वह केवल यह जांच करेगी कि क्या निरस्तीकरण संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं, वह इसके पीछे सरकार की मंशा की जांच नहीं करेगी।

बोला जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील दुशायंत दवे ने बताया कि 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा भंग होने के बाद सरकार की 370 को हटाने की शक्ति समाप्त हो गई।

सीजेआई ने बताया कि 1957 के बाद भी संविधान सभा को खत्म करने के बाद भी लगातार संवैधानिक आदेश कैसे पारित किए गए।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 2019 में संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 में कहा गया था कि अनुच्छेद में कोई भी बदलाव राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा से परामर्श करने के बाद ही किया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा 1957 में भंग कर दी गई थी। इसलिए याचिकाकर्ता बता रहे हैं कि निरस्तीकरण अमान्य था।

➔ बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, माफी नीति 'चयनात्मक' क्यों है?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात सरकार से पूछा कि कैदियों को रिहा करने की नीति "चुनिंदा" क्यों लागू की गई। न्यायमूर्ति नागरथा ने सवाल किया, "छूट की नीति को चुनिंदा तरीके से क्यों लागू किया जाता है? सुधार और पुनः एकीकृत होने का अवसर हर कैदी को दिया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ कैदियों को।"

बिलकिस बानो मामला - बिलकिस बानो के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने के दोषी 11 कैदियों को सरकारी कानूनों में बदलाव के बाद सजा सुनाई गई। इसे लेकर सीपीआई नेता सुभाषिनी अली और टीएमसी की महिया मोइत्रा ने जनहित याचिका दायर की थी।

➔ राष्ट्रपति मुर्मू ने युद्धपोत विंध्यगिरि का शुभारंभ किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग (जीआरएसई) में भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित तीन प्रोजेक्ट 17ए (अल्फा) फ्रिगेट की श्रृंखला में अंतिम विंध्यगिरी को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने इसे आत्मानिर्भर भारत प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बताया।

➔ **सीजेआई ने कहा, भारी आवंटन, तकनीक से न्यायपालिका में बदलाव आएगा**

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ता दुशयंत दवे के इस कथन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि निचली अदालतों को तकनीकी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा कि बजट के तहत ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिए आवंटित विशाल धनराशि न्यायपालिका को बदल देगी। बुद्धिमत्ता में लगभग ₹7000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

➔ **कौन प्रमुख राष्ट्रों से पारंपरिक चिकित्सा की शक्ति को अनलॉक करने के लिए कहता है?**

G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के हिस्से के रूप में पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस गेरेबेयन्स ने देशों से पारंपरिक चिकित्सा को अनलॉक करने की दिशा में काम करने और साक्ष्य और कार्रवाई आधारित सुझाव प्रदान करने का आग्रह किया, जिसे वैश्विक रणनीति में व्याख्यायित किया जा सकता है।

➔ **पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO वैश्विक केंद्र का मुख्यालय जामनगर, गुजरात में है।**

इसमें स्वास्थ्य मंत्री मनशुल्ह मांडविया ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया पोर्टल लॉन्च किया।

➔ **जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान ऐप लॉन्च किया गया**

केंद्रीय जल आयोग ने 'फ्लडवॉच' नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जो एक दिन पहले ही बाढ़ की संभावनाओं का पूर्वानुमान लगा सकता है। यह विभिन्न स्थानों पर बाढ़ पर सात दिवसीय सलाह भी प्रदान करता है।

World

➔ पाकिस्तान में चर्चों पर भीड़ के हमले के बाद 129 ईसाइयों को गिरफ्तार किया गया

पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम भीड़ द्वारा कुरान के उल्लंघन को लेकर ईसाई अल्पसंख्यकों के चर्चों और घरों पर हमला करने के बाद पुलिस ने रात भर में 129 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया।

पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले के जारांवाला शहर में एक चर्च को जला दिया गया, जबकि तीन में तोड़फोड़ की गई और कम से कम दो दर्जन घरों को आग लगा दी गई या बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना बुलानी पड़ी।

➔ आईएमएफ की महत्वपूर्ण समीक्षा से पहले चीन ने श्रीलंका की ऋण राहत के लिए समर्थन का आश्वासन दिया

श्रीलंका के प्रधान मंत्री दिनेश गुणवर्धने इस समय चीन के कुमिंग में हैं, जहां वह चीन दक्षिण एशिया प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि हैं।

दक्षिणी युन्नान प्रांत में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, चीनी विदेश मंत्री वांगयी ने बुधवार को "प्रतिज्ञा की कि चीन श्रीलंका को वित्तीय ऋण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करेगा"।

इससे पहले चीन ने श्रीलंका के विदेशी ऋण पर बातचीत के लिए इस साल मई में गठित 17 ऋणदाता देशों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है।

➔ अर्थव्यवस्था के संघर्ष के बीच शी ने धैर्य रखने का आह्वान किया

चीनी नेता शी जिनपिंग ने आर्थिक सुधार को लेकर जारी भाषण में धैर्य रखने का आह्वान किया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश भौतिकवाद और "आध्यात्मिक गरीबी" के कारण "बढ़ते संकट" में हैं।

मंगलवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि फैक्ट्री और उपभोक्ता व्यवसायों में मंदी आ रही है।

➔ यूक्रेन से नागरिक जहाज तुर्की के पास

यूक्रेन से एक नागरिक मालवाहक जहाज गुरुवार को बुल्गारिया के तट पर पहुंचा, जहाज रूसी नाकाबंदी की अवहेलना में नौकायन कर रहा था। जहाज का गंतव्य तुर्की है।

इससे पहले सप्ताहांत में रूस ने एक और जहाज पर हमला किया था।

Ports in black sea



- ➔ **लीबियाई मिलिशिया नेता को घातक संघर्षों के बाद रिहा कर दिया गया, जिसमें 55 लोग मारे गए थे।**
एक लीबिया. जिस मिलिशिया नेता की हिरासत के कारण हिंसा भड़की थी, उसे रिहा कर दिया गया है।
- ➔ **मलेशिया में सड़क पर विमान की भिड़ंत में मोटर चालकों सहित दस की मौत**
- ➔ **बिना अनुमति के फिल्म दिखाने पर ईरानी फिल्म निर्माता को जेल का सामना करना पड़ेगा**

संपादकीय

रूढ़िवादिता से लड़ना

लिंग टाइपकास्टिंग पर न्यायालय के दिशानिर्देश परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं

➔ संपादकीय के बारे में:

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए एक हैंडबुक जारी की है, जो न्यायिक निर्णय लेने और लिखने के लिए क्या करें और क्या न करें, बताते हुए असमानताओं से लड़ने का दावा करती है। यह पुस्तक न्यायाधीशों को विशेष रूप से महिलाओं के बारे में "गलत विचारों" की पहचान करने में मदद करती है और उन्हें उपयोग करने के लिए वैकल्पिक सही दुनिया प्रदान करती है। संपादकीय उन शब्दों के बारे में बात करता है।

➔ न्यायाधीशों द्वारा प्रयुक्त गलत शब्द और उनके विकल्प

अफेयर - शादी से बाहर का रिश्ता।

व्यभिचारिणी - वह महिला जो विवाहेतर संबंध बनाती हो

कई शब्द जो गलत या अपमानजनक हैं या गलत विचार देते हैं, उन्हें हटा दिया गया है "पवित्र" महिला, "कर्तव्यनिष्ठ" पत्नी, "गृहिणी"; सादे "महिला", "पत्नी" और "गृहिणी" का स्थान ले लिया गया है। "एफिमिनेट" और "फगोट" जैसे शब्द हटा दिए गए हैं।

दूसरी बात जो अदालत ने हटा दी है वह यह है कि जो महिला पारंपरिक कपड़े नहीं पहनती और धूम्रपान, शराब पीती है, वह परेशानी खड़ी कर रही है।

अदालत का यह मानना गलत है कि महिलाएं "अत्यधिक भावुक, अतार्किक होती हैं और निर्णय नहीं ले सकतीं।" यह भी एक रूढ़िवादी धारणा है कि सभी महिलाएं बच्चे चाहती हैं। दूसरी बात यह है कि महिला को घर का काम करना पड़ता है।

संपादकीय-2

नेक इरादे

कारिगरों को अपने उत्पादों के लिए तैयार बाजार की जरूरत है, न कि केवल किफायती ऋण की

➔ संपादकीय के बारे में

संपादकीय में पीएम विश्वक्रम मिशन के बारे में बात की गई है। संपादकीय में बताया गया है कि क्या अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है, कारिगरों को किन कमियों का सामना करना पड़ सकता है।

➔ पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में

इसके तहत सरकार ने पांच साल के लिए 13000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 18 श्रेणियों में कारिगर और शिल्पकार बहुत कम ब्याज दर पर दो किशतों में ₹3 लाख तक के लोन का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उनकी श्रेणियों के तहत कौशल और प्रौद्योगिकी में सुधार के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना से पांच वर्षों में लगभग 30 लाख कारिगरों और शिल्पकारों को मदद मिलेगी। कारिगरों में नाई, लोहार, राजमिस्त्री, बढई, खिलौना निर्माता शामिल हैं।

➔ पीएम विश्वनाथ के सामने चुनौतियां

संपादकीय उस गहरी चुनौती के बारे में बात करता है जो इन पारंपरिक कारिगरों के दुख का कारण है। उनके उत्पादों की मांग में कमी जिसके कारण उनकी खराब स्थिति हुई है। सरकार को इस चुनौती से निपटने की जरूरत है सरकार को इस चुनौती से निपटने की जरूरत है तभी पीएम विश्वकर्मा सफल होंगे।